

संक्षिप्त समाचार

फिल्म द साबरमती रिपोर्ट टैक्स फी-आदेश जारी

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। राज्य शासन ने श्री धीरज सरना द्वारा निर्देशित हिन्दी फोच में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को मध्यप्रदेश में टैक्स फी कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। मध्यप्रदेश में फिल्म को प्रदर्शन की अवधि 21 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक के लिये राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समुल्य राशि की प्रतिपूर्ति करते हुए दर्शकों को छुट्ट प्रदान की है। फिल्म के प्रदर्शन के लिए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की धन राशि को घटाकर दर्शकों को टिकट विक्रय किया जाएगा। फिल्म प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमाथारों/मल्टीफ्लोरेस्ट के प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। सेवा प्रदाय पर देय एवं भुगतान किए गए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के अंश के बराबर की राशि को राज्य शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

मातृछाया व वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती ताकुर और महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निमला भूरिया ने आयकर भवन के पीछे स्थित मातृछाया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मातृछाया के संचालक से बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं को विस्तृत से जाना और इसे व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये आवश्यक निर्देश दिये। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती ताकुर ने जे.पी. अस्सलाल परिसर स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्यमंत्री व विभागीय मंत्री ने सेंटर के कर्मचारियों से यहां आने वाली पीड़िताओं को दी जाने वाली कानूनी सलाह व उनको दिये जाने वाले उपचार संबंधी जानकारी प्राप्त की। सेंटर के संचालन से जुड़ी आवश्यक जानकारी लीं और सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की सुरक्षा व्यवस्था एवं बुधवार को भोपाल स्थित आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागृह में उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य

आयुष मंत्री परमार की अध्यक्षता में हुई पुरस्कार चयन समिति की बैठक

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्द्र सिंह परमार की अध्यक्षता में बुधवार को प्रधानमंत्री और अधिकारी एवं आयुष विभाग अंतर्गत पुरस्कार चयन समिति की बैठक हुई। बैठक में पंडित उद्धवदास मेंता वैद्यशास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्पादन पुरस्कार वर्ष-2022 के लिए पुरस्कार चयन समिति ने व्यापक विचार मंच किया। बैठक में सर्वसम्मति से वर्ष-2022 के पुरस्कार के लिए नाम का चयन किया गया। आयुष मंत्री श्री परमार ने अंडांड कर्तव्य विभागीय समीक्षा बैठक हुई।

अनियमितता, गंभीर लापरवाही के चलते बिजली कंपनी के 4 इंजीनियर निलंबित

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कार्य में अनियमितता और कार्य में गंभीर लापरवाही पाए, जाने पर कठोर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 4 इंजीनियरों को तकलीफ प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित इंजीनियरों में इंदौर संचारण संधरण संभग के कार्यालय यंत्री श्री अधिकारी रंजन, भौंगसाला बिजली वितरण केंद्र प्रभारी सहायक यंत्री श्री राहुल खत्री, भौंगसाला वितरण केंद्र के कनिष्ठ यंत्री श्री शैलेंद्र पाटकर और चिकलौंडा (बेटमा) बिजली वितरण केंद्र प्रभारी कनिष्ठ यंत्री श्री प्रेम सिंह कनेश शामिल हैं। श्री रंजन को निलंबित अवधि में सरकारी कार्यालय इंदौर, श्री खत्री को बुढाहानपुर सरकारी कार्यालय, श्री पाटकर को सरकारी सहायक यंत्री श्री राहुल खत्री, भौंगसाला वितरण में अंदेच दिया गया है। इसी के साथ श्री ज्ञानेंद्र कुमार गौड़ को एसटीसी इंदौर ग्रामीण से हटाकर कारपैरिट कार्यालय भेजा गया है। श्री गौड़ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कार्मिकों से नियमों, प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करने एवं समय पालन के साथ ही अपने कर्तव्यों का निर्देश दिये हैं।

भारत केंद्रित शिक्षा से समृद्ध पाठ्यक्रम निर्माण के लिए, भारतीय दृष्टि की आवश्यकता - मंत्री परमार

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। भारत का ज्ञान, हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन में भारत केंद्रित शिक्षा से समृद्ध आदर्श पाठ्यक्रम निर्माण के लिए, लेखकों में गहन भारतीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। फिल्म के प्रदर्शन के लिए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की धन राशि को घटाकर दर्शकों को टिकट विक्रय किया जाएगा। फिल्म प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमाथारों/मल्टीफ्लोरेस्ट में फिल्म के लिए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की धन राशि को घटाकर दर्शकों को टिकट विक्रय किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का मूल ध्येय, श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करना है, इसके साथ अपनी सहायता देना होगा। यह बत्त उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्द्र सिंह परमार ने बुधवार को भोपाल स्थित आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागृह में स्वत्व एवं राष्ट्रीय निर्माण का भाव जागृत एवं स्थापित होगा।

में आयोजित केंद्रीय अध्ययन मंडल की बैठक एवं कार्यशाला के शुरूआत अवसर पर कही।

मंत्री श्री परमार ने भारतीय ज्ञान परम्परा के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। श्री परमार ने कहा कि पाठ्यक्रम की पहली इकाई में ही भारतीय दृष्टिकोण की पुस्तकालय के लिए कार्यशाला के साथ होगी। विद्यार्थियों को यह ज्ञान देना चाहिए कि विश्व मंच पर इतिहास में भारत की कथा साथ रही है।

भारत का ज्ञान विश्व मंच पर सबसे पुराना



ज्ञान है, इसा से भी हजारों वर्षों पूर्व, भारतीय समाज में सर्वत्र विद्यमान ज्ञान परम्परा का, पाठ्यक्रमों में भारतीय दृष्टिकोण का पुस्तकालय के लिए, हमें हीनामंत्री ज्ञान परम्परा से पाठ्यक्रमों से समावेश करना होगा। आयुष मंत्री श्री परमार ने कहा कि भारतीय दृष्टि से पाठ्यक्रमों में सामावेश करना होगा।

शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने कहा कि विश्व भर में भारत आध्यात्म का केंद्र रहा है। मानवता लोककल्याण, पुरातन से ही भारतीय दृष्टिकोण रहा है। पाठ्यक्रमों में भारतीय दर्शन वसुधेव कुटुंबकां को समावेश करने की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में भारतीय ज्ञान का अनंत भंडार है। इतिहास, अर्थशास्त्र, फिजिक्स, कैमिस्ट्री एवं गणित सहित सभी विषयों में भारतीय पुरातन ज्ञान के तथ्यपूर्ण संदर्भों पर सोध एवं अनुसंधान करते हुए, सही परिप्रेक्ष्य में तथ्यपूर्ण संदर्भों की जनमानस के समक्ष लाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारी ज्ञान संचालन के तथ्यों एवं उदाहरणों के साथ होगा। श्री परमार ने कहा कि भारतीय दृष्टि परंपराओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, युगानुकूल परिप्रेक्ष्य में भारतीय ज्ञान पर गर्व होगा।

विभागीय योजनाओं व गतिविधियों का प्रचार प्रसार जिले स्तर पर भी किया जाना आवश्यक-केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती गङ्कर



मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती ताकुर ने एं.पी. अस्सलाल परिसर स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय राज्यमंत्री व विभागीय मंत्री ने सेंटर के कर्मचारियों से यहां आने वाली पीड़िताओं को दी जाने वाली कानूनी सलाह व उनको दिये जाने वाले उपचार संबंधी जानकारी प्राप्त की। सेंटर के संचालन से जुड़ी आवश्यक जानकारी दिए। अस्सलाल के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की सुरक्षा एवं आयुष मंत्री सुश्री निमला भूरिया ने आयुष विभाग अंतर्गत पुरस्कार चयन समिति ने व्यापक विचार मंच किया। बैठक में सर्वसम्मति से वर्ष-2022 के पुरस्कार के लिए नाम का चयन किया गया। आयुष मंत्री श्री परमार ने अंडांड उद्धवदास मेहता वैद्यशास्त्री आयुर्वेद सेवा सम्पादन पुरस्कार वर्ष-2023 के लिए अनुशासन समिति के बैठक में विभागीय समीक्षा बैठक हुई।

खेल भावना जीवन में रखती है अहमियत- मंत्री सारंग

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कर्तव्यालय सारांग ने कहा है कि खेल हमें में हार और जीत को समान बाल खेल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के हरसंभव प्रयास कराये जाने को आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का प्रधानमंत्री की मंशानुरूप प्रचार प्रसार कराया जाना चाहिए।

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कर्तव्यालय सारांग ने जीवन में खेल विभाग की व्यवस्था एवं समन्वय कराये जाने के हरसंभव प्रयास कराये जाने को आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का प्रधानमंत्री की मंशानुरूप प्रचार प्रसार कराया जाना चाहिए।

मीडिया ऑ

विचार

बद से बदतर होती जा रही है चुनावी बयानबाजी

महाराष्ट्र और झारखण्ड में उपीदवारों की किस्मत तय होने के साथ ही, एक कटु और बेबाक प्रचार अभियान का अंत हो गया है। दोनों राज्यों में चुनावों का अंतिम परिणाम चाहे जो भी हो, यह प्रचार अभियान इतिहास में अब तक के सबसे सांप्रदायिक और विभाजनकारी अभियानों में से एक के रूप में दर्ज किया जाएगा। मुझे याद है कि मैंने पिछले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के समाप्त होने के ठीक बाद भी ऐसा कहा था। दुर्भाग्य से, खासकर सांप्रदायिक रंग के साथ राजनीतिक बयानबाजी का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है और अभी-अभी सम्प्रहुए चुनाव अभियान को अब सबसे ज्यादा सांप्रदायिक कहा जा सकता है। दोनों राज्यों, खासकर महाराष्ट्र में हुए चुनावों में भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगियों तथा कांग्रेस एवं उसके गठबंधन सहयोगियों दोनों के लिए बहुत कुछ दाव पर लगा था। हरियाणा चुनावों के आश्र्यजनक परिणाम, जिसमें भाजपा ने सभी को गलत साबित कर दिया और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया, ने महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाले अभियान को बढ़ावा दिया। हालांकि, जाहिर है कि भाजपा देश के सबसे समृद्ध और दूसरे सबसे बड़े राज्य को जीतने के लिए कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। कांग्रेस और अन्य गठबंधन दलों को अंतीम में नरेंद्र मोदी के लिए 'मौत का सौदागर' जैसे नारे लगाने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने सांप्रदायिक बयानों और नारों से मीलों आगे हैं। उनके नारे जैसे 'बंटेंगे तो कटेंगे' और 'एक हैं तो सेफ हैं' में स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक रंग है जिसे एक बच्चा भी समझ सकता है। अधिक बच्चे पैदा करने वाले या जिनके सदस्य 'घुसपैठिया' हैं और जो मंगलसूत्र, जमीन और सोना छीन लेंगे, उनका संदर्भ स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक रंग देता है। इससे पहले लोकसभा चुनावों के दौरान, मादी ने दाव किया था कि विपक्ष को मिलने वाला हर बोट हिंदुओं द्वारा अर्जित धन का उपयोग उन मुसलमानों को वितरित करने के लिए किया जाएगा जिनके अधिक बच्चे हैं और जो घुसपैठिए हैं, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को हिंदू महिलाओं के 'मंगलसूत्र' भी वितरित कर सकती है। सांप्रदायिक पहलू को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने भाषणों में 'घुसपैठियों' को दीमक बताते रहे हैं और आदिवासियों से कहते रहे हैं कि वे अपनी मासूम बेटियों को अपनी तीसरी या चौथी पत्नी बना लेंगे। विडब्बना यह है कि पार्टी के नेता जाति जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस और कुछ अन्य दलों की आलोचना करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि यह 'विभाजनकारी' है और इससे सामाजिक तनाव पैदा होगा। सबसे मुख्य और सबसे सांप्रदायिक नेताओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्ता सरमा शामिल हैं। वे कभी भी विकास या प्रगति या यहां तक कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों की उपलब्धियों के बारे में बात नहीं करते हैं।

कानूनी दायरे में कैसे लाए जाएं चुनावी वायदे

अमेश चतुर्वेदी

चुनाव घोषणा पत्रों में किए वायदों को पूरा न कर पाने को लेकर सा में आने वाला हर राजनीतिक दल मतदाताओं और विपक्षी दलों के निशाने पर रहा है। मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता के चलते इन आलोचनाओं से बचने के लिए राजनीतिक दलों ने अब चुनाव घोषणा पत्र जारी करना बंद कर दिया है। 2012 के आर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में उत्तरी कांग्रेस ने राज्य के लिए विजन डायरेंट जारी किया। इसके बाद सभी दलों ने चुनाव घोषणा पत्र के शीर्षक को तकरीबन त्याग दिया। अब भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के पहले संकल्प पत्र जारी करती है तो कांग्रेस अब गारंटियां देने लगी हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पांच गारंटी देने का वादा किया। जो उसके लिए बहुत हिट रहा। अब पार्टी गारंटी देती है, दृष्टि पत्र प्रस्तुत करती हैं और संकल्प पत्र प्रस्तुत करती हैं। गारंटी और संकल्प जैसे शब्द एक तरह से गवाह हैं कि राजनीतिक दलों के वायदों को लेकर मतदाताओं का एक बड़ा अब आलोचनात्मक रूप ही नहीं रखता है, बल्कि उन पर भरोसा भी नहीं



घोषणा पत्र भले ही अब गारंटी या दृष्टि या संकल्प पत्र में तबदील हो गए हों, लेकिन अब भी उनकी साथ नहीं बन पाई है। इसकी वजह यह है कि कई बार राजनीतिक दल बोटरों को लुभाने के चक्र में ऐसे भी वायदे कर डालते हैं, जिन्हें पूरा कर पाना उनके लिए संभव नहीं होता। राजनीतिक दल भी जानते हैं कि संकल्प, दृष्टि या गारंटी पत्र में दिए वायदों को शत-प्रतिशत पूरा करना संभव नहीं है और अगर वे करते भी हैं तो सकारी अथवावस्था का चरमरा सकती है। परं वे वायदे करते हैं या कह सकते हैं कि सता के लक्ष्य को लेकर चलने वाली माजूदा राजनीति की यह मजबूरी भी है।

चुनाव घोषणा पत्रों और आज के दृष्टि और संकल्प पत्रों में किए वायदों और उन्हें लागू किए जाने को लेकर ठोस शोध जरूरी है। लेकिन मोटे तौर पर इन्हें दर्ज ज्यादातर वायदे पूरे हो ही नहीं पाते। इसलिए मतदाताओं के एक वर्ग अलग ढूँग से सोचने लगा है। मतदाताओं के एक वर्ग का मानना है कि चाहे जिस भी फैम में चुनाव घोषणा पत्र जारी हों, उन्हें उपभोक्ता कानून के दायरे में लाना चाहिए। जिस तरह किसी प्रोडक्ट का कानून के दायरे में लाना चाहिए। उसके लिए उन्हें निर्माता अपने प्रोडक्ट को लेकर गारंटी या वारंटी देता है, और जब वे पूरे नहीं होते तो उसके प्रोडक्ट खरीदने

वाले उत्पादक के खिलाफ उचित फोरम में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसी तरह चुनावी घोषणा पत्रों को लेकर भी कानून नहीं होता। राजनीतिक दल भी जानते हैं कि एक फैरम ऐसा भी होना चाहिए, जिसे कानूनी ताकत हासिल हो और जो चुनावी वायदाखिलाफी की सुनवाई कर सके।

चुनाव घोषणा पत्रों की स्थिति संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही है। नीति निर्देशक तत्व राज्य से लोक हित के तमाम कदम उठाने को लेकर उम्मीद तो करता है, लेकिन राज्य के लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं बनता। नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य या सरकार कदम नहीं उठाती तो किसी को भी अदालत में इसकी शिकायत की ना तो अनुमति है और आना ही कोई अदालत में सुनवाई कर भी सकती है। चुनाव घोषणा पत्रों की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनाव घोषणा पत्रों को लेकर अदालतों के सामने सवाल नहीं उठते। चुनाव घोषणा पत्र को लेकर वायदे खूब ही रहे और हर राजनीतिक दल अपने ढांग से लागू भी कर रहा है। भले ही राज्य के खाली जानवारों की हालत खात्मा ही क्यों नहीं हो जा रही है। लेकिन लेह यह भी सच है कि उस पर खरूच होने वाले देश के सोत को लेकर जानकारी नहीं दी जा रही है। साफ है कि चुनाव आयोग की गाइड लाइन इस संदर्भ में नाकाम लग रही है। मौजूदा आर्थिकी में लाभ पर जारी है, रोजगार का सवाल लगातार पीछे छूटा जा रहा है। इसे उलटबांसी ही कहेंगे कि राजनीतिक दल इसी आर्थिकी को आगे बढ़ाने के साथ ही हवाई वायदों की फेरिस्त भी जारी करते रहते हैं। चूंकि वायदों के लिए जानकारी नहीं देते। मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता का दबाव ही है कि कल्याणकारी योजनाओं को लेकर वायदे खूब ही रहे और हर राजनीतिक दल अपने ढांग से लागू भी कर रहा है। भले ही राज्य के खाली जानवारों की हालत खात्मा ही क्यों नहीं हो जा रही है। लेकिन लेह यह भी सच है कि उस पर खरूच होने वाले देश के सोत को लेकर जानकारी नहीं दी जा रही है। साफ है कि चुनाव आयोग की गाइड लाइन इस संदर्भ में नाकाम लग रही है। मौजूदा आर्थिकी में लाभ पर जारी है, रोजगार का सवाल लगातार पीछे छूटा जा रहा है। इसे उलटबांसी ही कहेंगे कि राजनीतिक दल इसी आर्थिकी को आगे बढ़ाने के साथ ही हवाई वायदों की फेरिस्त भी जारी करते रहते हैं। चूंकि वायदों के लिए जानकारी नहीं देते। मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता का दबाव ही है कि कल्याणकारी योजनाओं को लेकर वायदे खूब ही रहे और हर राजनीतिक दल अपने ढांग से लागू भी कर रहा है। भले ही राज्य के खाली जानवारों की हालत खात्मा ही क्यों नहीं हो जा रही है। लेकिन लेह यह भी सच है कि उस पर खरूच होने वाले देश के सोत को लेकर जानकारी नहीं दी जा रही है। साफ है कि चुनाव आयोग की गाइड लाइन इस संदर्भ में नाकाम लग रही है। एसे क्या हो जा रहा है? निश्चित तौर पर यह विकल्प होगा कि वे उल्लंग लोगों को न चुनें जो जनता की राय से अलग हैं। लेकिन जिबाब ना मैं हूँ और किसी नहीं है। एसे क्या हो जा रहा है? निश्चित तौर पर यह विकल्प होगा कि वे शब्द, जो उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों पर अदालती चावुक के तर्क के विरोध में दिया था। तब उन्होंने जनता की ताकत पर भरोसा जाता है दुप्त जाना था कि पांच साल में एक बार जब चुनाव होंगे, तब मतदाताओं के लिए यह विकल्प होगा कि वे शब्द, जो उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों पर अदालती चावुक के तर्क के विरोध में दिया था। तब उन्होंने जनता की ताकत पर भरोसा जाता है दुप्त जाना था कि पांच साल में एक बार जब चुनाव होंगे, तब मतदाताओं के लिए यह विकल्प होगा कि वे शब्द, जो उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों पर अदालती चावुक के तर्क के विरोध में दिया था। तब उन्होंने जनता की ताकत पर भरोसा जाता है दुप्त जाना था कि पांच साल में एक बार जब चुनाव होंगे, तब मतदाताओं के लिए यह विकल्प होगा कि वे शब्द, जो उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों पर अदालती चावुक

